

प्रेषक,

आर0डी0 पालीवाल
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महाधिवक्ता
उत्तराखण्ड
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 07 सितम्बर, 2009

विषय- महाधिवक्ता कार्यालय में वाद अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षक को सचिवालय से समकक्षता के आधार पर उच्चीकृत वेतनमान की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या - 162/वे0संशो/2009 दिनांक 6-3-2009 एवं वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 77/xxvii(7)/2009 दिनांक 1 मार्च, 2009 का संदर्भ लेने का कष्ट करें ।

2- राज्य विधि अधिकारी कार्यालय(महाधिवक्ता कार्यालय) के कार्मिकों की यथासम्भव मा0 उच्च न्यायालय के कार्मिकों को अनुमन्य वेतनमान के अनुरूप वेतनमान दिये जाने का निर्णय शासनादेश संख्या - 833/सात-उच्च न्याय/73-67 दिनांक 11-9-1974 द्वारा लिया गया तथा उच्च न्यायालय के कार्मिकों को राज्य सचिवालय के अनुरूप वेतन एवं भत्ते दिये जाने का निर्णय शासनादेश संख्या 3021/263/65 दिनांक 20 मार्च, 1968 द्वारा लिया गया । यह समता केवल तभी अनुमन्य होगी जब महाधिवक्ता कार्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति पारदर्शी प्रणाली के अन्तर्गत विज्ञापन प्रकाशित कर नियमानुसार परीक्षा आयोजित करने के उपरान्त श्रेष्ठता के आधार पर की गयी हो ।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महाधिवक्ता कार्यालय के वाद अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षक के दिनांक 1-1-1996 से लागू वेतनमान रू0 6500-10500 को निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन उच्चीकृत किया जाता है :-

क्रम सं०	पद	वर्तमान वेतनमान	संशोधित वेतनमान	सादृश्य बैण्ड	सादृश्य ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6
1	वाद अधीक्षक / सहायक अधीक्षक	6500- 10500	7500-12000 8000- 13500 (चार वर्ष पूर्ण करने पर)	वेतन बैण्ड-2 वेतन बैण्ड-3	4800 5400 (चार वर्ष पूर्ण करने पर)

(1) उक्त संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान दिनांक 1-1-2006 से प्राकल्पित आधार पर उच्चीकृत करते हुये वास्तविक लाभ दिनांक 1-4-2009 से दिया जायेगा । स्पष्टतः वास्तविक लाभ की तिथि 1-4-2009 से पूर्व का एरियर देय नहीं होगा परन्तु इस वेतनमान का लाभ प्रदान करने से पूर्व महाधिवक्ता द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि श्री बी०एल० ध्यानी, वाद अधीक्षक, श्री राकेश कुमार , सहायक अधीक्षक एवं श्री जयकृष्ण लखेड़ा, सहायक अधीक्षक की नियमानुसार नियमित नियुक्ति/पदोन्नति हुई है और इनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक है और इनके विरुद्ध कोई शिकायत /जांच लम्बित नहीं है। इन कार्मिकों के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्मिक को भविष्य में उक्त लाभ की अनुमन्यता बनने पर उस पदधारक की नियुक्ति सम्बन्धित सेवा नियमावली/राज्य सरकार के विभागों के अधीन नियमानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने तथा उसके समस्त अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने पर न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति से ही उक्तवत वेतनमान अनुमन्य होगा ।

(2) वाद अधीक्षक/सहायक वाद अधीक्षक को उच्चतर वेतनमान मिलने के फलस्वरूप उनकी कार्यकुशलता एवं क्षमता में वृद्धि अपेक्षित है । अनुस्मारकों, लम्बित पत्रावलियों एवं संदर्भों का कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से किये जायेगे ।

(3) दिन प्रतिदिन कार्यों में प्रयुक्त होने वाले आदेश एवं नियम कम्प्यूटर पर रखे जायेगे ताकि आवश्यकतानुसार पत्रावली पर उनका उद्धरण अंकित किया जा सकें ।

(4) नैत्यक किस्म के कार्य वाद अधीक्षक/सहायक अधीक्षक के स्तर पर ही निबटाये जायेगें ।

(5) अनुभाग का **Reference Register** कम्प्यूटर पर ही रखा जायेगा ।

(6) वाद अधीक्षक/सहायक अधीक्षक द्वारा अपने अनुभाग पर प्रभावी नियंत्रण रखा जायेगा एवं अधीनस्थों के कार्य का मूल्यांकन कर आख्या महाधिवक्ता को प्रस्तुत की जायेगी ।

(7) महाधिवक्ता द्वारा प्रत्येक छमाही में अनुभागों का निरीक्षण कर अधीक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा ।

4- उपरोक्त अधिकारियों को नॉन फक्शनल वेतनमान रू० 8000-275-13500 का लाभ प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप उन्हें समयमान वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत आगे लाभ अनुमन्य नहीं होगा ।

5- उपरोक्त अनुमन्य कराये गये नॉन फक्शनल वेतनमान से सम्बन्धित वाद अधीक्षक/सहायक अधीक्षक का वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-22 ए(1) के अनुसार किया जायेगा ।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00- आयोजनेत्तर-114-विधि सलाहाकार और परामर्शदाता(काउन्सिल)- 03-महाधिवक्ता-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामों में डाला जायेगा ।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2140/xxxvii(7)/2009 दिनांक 2 सितम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर0डी0 पालीवाल)
सचिव,

संख्या- 86 (1)/xxxvi(1)/09-237जी0/2001तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस-सी-1/105 इन्दिरा नगर, देहरादून ।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारपुर रोड, माजरा, देहरादून ।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
- 4- वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन ।
- 5- विभागीय आदेश पुस्तिका ।
- 6- एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बोनाल)
अपर सचिव,